भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2273

11 दिसम्बर, 2015 को उत्तर के लिए

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

2273.श्री पी. कुमार:
श्री दिनेश त्रिवेदी:
श्री राहुल शेवाले:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री हरीश मीना:
श्रीमती कमला पाटले:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री विनायक भा ऊराव राऊत:
श्री रायपति साम्बासिवा राव:
श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान:
श्री पी. आर सेनथिलनाथन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु आवंटित बजट का पूर्ण रूप से उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष हेतु आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके बल-वार क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रक्षा बलों के राजस्व व्यय का ब्यौरा क्या है और सेना में जनशक्ति बनाए रखने के लिए सरकार पर कितनी औसत जीवन अवधि लागत आती है;

(घ) क्या सशस्त्र बलों के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दने के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और अधिग्रहण प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने तथा देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) : एक विवरण संलग्न है ।

लोक सभा में दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2273 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): वर्ष 2014-15 के दौरान रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत	बचत संशोधित प्राक्कलन के % के रूप में
2014-15	75,148.03	66,151.73	65,862.38	289.35	0.44

वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लघु बचतों के संचयी प्रभाव के रूप में केवल 289.35 करोड़ रुपए (आबंटन का 0.44%) की लघु राशि ही बिना खर्च रही । तथापि, वर्ष 2014-15 को दौरान खर्च के सेना-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

सेवा	वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
सेना	16,927.35	13,867.40
नौसेना	17,075.24	20,905.54
संयुक्त स्टाफ	330.75	280.05
वायुसेना	31,818.39	30,809.39
कुल	66,151.73	65,862.38

(ग) (i) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान रक्षा सेनाओं के राजस्व व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
2012-13	1,13,828.66	1,08,924.89	1,11,276.66
2013-14	1,16,931.41	1,24,799.89	1,24,374.30
2014-15	1,34,412.05	1,40,404.76	1,36,807.20
2015-16	1,52,139.00	प्रक्रियाधीन	95,940.67 (नवम्बर 2015 तक व्यय)

(ii) सेना कार्मिकों के संबंध में वार्षिक प्रति व्यक्ति आवर्ती लागत (वेतन तथा भत्तों, सफाई व्यवस्था एवं गर्म मौसम, राशन एंव ईंधन तेल तथा लूब्रीकेंट, आवास, परिवहन,

चिकित्सा, वस्त्र एवं उपकरण, प्रशिक्षण लागत, तथा विविध लागत को शामिल करते हुए) इस प्रकार है:-

(क) अफसर:- 11,96,999.00-रु.-20,83,117.00 रु. (रैंक प्रोफाइल के अनुसार)

(ख) जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर:- 7,88,687.00 रु.

(ग) अन्य रैंक :- 5,26,064.00 रु.

(घ) और (ङ) : रक्षा सेना का आधुनिकीकरण खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है । यह प्रक्रिया एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना, पंचवर्षीय सैन्य पूंजीगत अर्जन योजना तथा वार्षिक अर्जन योजना पर आधारित होती है ।

सरकार सुरक्षा परिदृश्य की निरन्तर समीक्षा करती है और तदनुसार उपयुक्त रक्षा उपस्कर शामिल करने का निर्णय लेती है ताकि सशस्त्र सेनाओं को तैयारी की स्थिति में आधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित रखा जा सके जोकि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी विक्रेताओं से अधिप्राप्ति के जरिए किया जाता है ।

रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होती है । डीपीपी-2013 में अधिप्राप्ति प्रक्रिया के लिए समय-सीमाएं समाहित हैं । इसमें 'खरीदो (भारतीय)', 'खरीदो और बनाओ (भारतीय) ' और 'बनाओ' श्रेणीकरण को पूंजीगत अधिप्राप्ति में अधिमानी वरीयता दी गई है । अर्जन प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए किए गए उपायों में आवश्यकता की स्वीकृति लेने से पूर्व सैन्य गुणात्मक आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया जाना, आवश्यकता की स्वीकृति की वैधता को कम करके एक वर्ष किया जाना, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, सामूहिक रूप से निर्णय लेना तथा संविदाओं के संचालन में देरी के लिए विक्रेता पर परिनिर्धारित नुकसानी लगाना शामिल हैं ।

रक्षा सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्लेटफार्मों, हथियार प्रणालियों, सेंसरों, उपस्करों का स्वदेशीकरण डीआरडीओ द्वारा इसके मिशन मोड (एमएम) श्रेणी परियोजना के अंतर्गत किया जाता है । वर्तमान स्थिति के अनुसार डीआरडीओ के पास 36220 करोड़ रुपए मूल्य की एमएम परियोजनाएं चल रही हैं । डीआरडीओ के पास इन परियोजनाओं की उप-प्रणालियों के सहयोग तथा भावी प्रौद्योगिकी विकास के लिए 7243 करोड़ रु. मूल्य की परियोजनाएं चल रही हैं और इन्हें प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं कहा जाता है ।

*****